करनाल शुगर मिल में बिकती हैं नौकरियां

करनाल (म.मो.) करनाल एस डी एम राजीव मेहता जो 2008 से 2013 तक स्थानीय चीनी मिल के प्रबन्ध निदेशक रह चुके हैं, और आईएएस बनने की तैयारी में हैं, के काले कारनामों के बारे में मनोहर लाल खट्टर को लगातार सीएम विंडो पर दरखास्तें दी जा रही हैं। लेकिन इन पर जांच के नाम पर केवल लीपा-पोती ही की जा रही है। लीपा-पोती हो भी क्यों नहीं जब जांच करने वाला अतिरिक्त उपायुक्त गिरीश अरोड़ा खूद उनके मित्रवत हों। पड़ोसी एवं सहकर्मी होने के नाते इतनी लीपा-पोती तो चलती है। विशेषकर प्रशासन में जहां भ्रष्टाचार ही नियम है।

करनाल चीनी मिल में अपनी 5 वर्ष की तैनाती के दौरान अन्य घोटालों के अलावा राजीव मेहता ने जो नौकरियां बेची हैं, उनमें से तीन पुख्ता सुबूत आर टी आई के द्वारा 'मज़दूर मोर्चा' के हाथ लगे हैं। सर्वप्रथम, इस मिल में एक प्रशिक्षित स्टेनो-टाइपिस्ट की जगह विज्ञापित की गयी। इस पद के लिये अभ्यार्थी का अपने विषय में उचित प्रशिक्षण प्राप्ति का प्रमाणपत्र होना चाहिये, वह भी किसी अच्छे मान्यता प्राप्त संस्थान से। परन्तु इनका चयन करने वाली कमेटी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे स्टेनोग्राफी का ज्ञान हो। दूसरे, मिल के लिये विज्ञापित सुरक्षा अधिकारी के पद हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गयी थी। इसके अलावा उसका पूर्व सैनिक होने के साथ-साथ कुछ आवश्यक प्रशिक्षण होने की शर्त भी रखी गयी थी। इस पद के लिये भी राजीव मेहता ने 38 वर्षीय, पूर्णतया सुप्रशिक्षित अभ्यार्थी को छोड़कर एक 45 वर्षीय को नियुक्त प्रदान कर दी। नियमानुसार बतौर एम डी राजीव मेहता को विज्ञापित शर्तों का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फ़िर भी उन्होंने यह घोटाला कर दिया।

तीसरे, मिल के लिये एक क़ानूनी सहायक (वकील) की नियुक्ति में भी घोर अनियमितता बरती गयी है। भीतरी जानकारी रखने वालों के अनुसार इस पद पर नियुक्त किये गये रमन के शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज़ों की अभी तक भी कोई तसदीक एवं पुष्टि नहीं कराई गयी। सूत्रों को पूरा विश्वास है कि इनका भी हाल-चाल कुछ दिल्ली के पूर्व क़ानून मन्त्री तोमर जैसा ही है। स्थानीय बार एसोसिएशन ने भी शायद इसी आधार पर इन्हें सदस्यता प्रदान नहीं करी।

इन हालात में यदि राजीव मेहता पर नौकरियां बेचने का आरोप लगता है तो क्यों न उसे सही मान लिया जाय? मिल में निकलने वाली नियुक्तियों को विज्ञापित करने का तरीका भी मेहता जी का न्यारा ही था। इस काम के लिये वे अखबारों का चयन भी खुद ही करते थे और ऐसा करते थे कि कम से कम लोग़ों को ही इसकी भनक लग सके।

सर्वविदित है कि नौकरियों की रेवड़ियां बांटने के जुर्म में चौटालों समेत पचासों अधिकारी/कर्मचारी जेल की हवा खा रहे हैं। दरअसल जब तक किसी भी घोटालेबाज़ को पकड़ कर जेल नहीं भेजा जाता वह अपने आपको सबसे शातिर एवं बुद्धिमान समझता है। भ्रष्टाचार समाप्त करने एवं ईमानदारी का दम भरने वाले मुख्यमंत्री खट्टर देखते हैं इस मामले में क्या करते हैं।

नौकरियों के अलावा मिल के लिये खरीदो-फ़रोख्त में भी राजीव मेहता ने बड़े गोलमाल कर रखे हैं। एक पुख्ता जानकारी के अनुसार इन्द्री कसबे में राजीव मेहता का सर्वशिक्षा मन्दिर नाम से एक स्कूल है। 2010 में स्कूल के लिये एक फ़र्जी ट्रस्ट बना कर करीब साढे तीन एकड़ ज़मीन खरीदी गयी थी। उस वक्त ज़मीन का बाज़ार भाव डेढ करोड़ प्रति एकड़ का था। जाहिर है यह सब काली कमाई का ही खेल था। इसमें एक शेड बनवाने के लिये इन्होंने वर्ष 2011-12 में जगाधरी के एक कबाड़ी से स्क्रैप लोहा खरीदा। जब वह स्क्रैप शेड बनाने के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया तो उसे मिल के खाते में खरीद लिया गया और जगाधरी की ही एक फ़र्म एस.एस.बी एसोसिएट के माध्यम से स्कूल के लिये नया स्टील खरीद लिया गया। इसका 3 लाख 58 हज़ार पांच सौ 78 रुपये का बिल नं. 64 दिनांक 21.09.11 मिल के खाते में डाल दिया गया। इस खरीद में स्टील का जो भाव दिखाया गया है वह बाजार भाव से 15 से 20 रुपये अधिक है। इसके अलावा मिल को जो 2.50 रूपए प्रति किलो के हिसाब से उत्पादक शुल्क वापस मिलना था वह भी मारा गया।

राजीव मेहता द्वारा किये गये अनेकों छोटे-बड़े घोटालों की ये तो मात्र कुछ बानगियां हैं, यदि ढंग से जांच की जाय तो बहुत कुछ सामने आयेगा जिससे यह भी पता चल जायेगा कि निजी क्षेत्र में सोना उगलने वाली चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में घाटा क्यों कमाती है?

बढता जा रहा है सट्टेबाज़ों व ड्रग माफ़िया का धंधा

फ़रीदाबाद (म.मो.) जहां एक तरफ़ फ़रीदाबाद पुलिस कमिश्नर शहरवासियों को एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ़ उनके अपने ही विभाग के अधिकारी उनके प्रयासों को पलिता लगाते हुए काले धंधे-वाजों से हफ़्ता वसूली में लगे हुए हैं। जिसके चलते शहर सट्टेबाजों, शराब तस्करो, ड्रग्स माफ़ियों, जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले माफ़ियों की गिरफ़्त में फंसता नज़र आ रहा है। सूत्रों अनुसार थाना एनआईटी क्षेत्र के अंतर्गत करीब 2 दर्जन से अधिक शराब माफ़िया धड़ल्ले से अवैध शराब बेचने का धंधा कर रहे हैं। दर्जनों से अधिक सट्टे की पर्ची लिख स्कूली बच्चों व युवाओं को मोटी रकम कमाई का लालच देकर उन्हें बर्बाद करने में लगे हुए हैं साथ ही एनआईटी के 5 नम्बर में ही आधा दर्जन के करीब वेश्यावृत्ति के अड्डे भी जमकर चल रहे हैं।

अजरोदी गांव में रहने वाला एक ड्रग्स माफ़िया एनआईटी क्षेत्र में धड़ल्ले से अफ़ीम, चरस, गांजा का धंधा कर रहा है जोकि पहली अफीम 2000 रुपये तोला, दूसरा 1500 रुपये तोला। पहला चरस 2000 तोला, दूसरा 1500 रुपये व गंजे की पुड़िया। 10 ग्राम की 120 रुपये 3 ग्राम की 40 रुपये 5 ग्राम की 70 रुपये में बेच रहा है ये काम चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम दिन दिहाड़े चल रहा है। अजरौंदी गांव का यह धंधेबाज़ चोटीवाला के नाम से मशहूर है जो कि एनआईटी नीलम पुल के नीचे, सेन्ट्रल अस्पताल व मैट्रो सर्विस स्टेशन के पास अपने गोरखधंधों को अंजाम दे रहा है। इसके पास करीब आधा दर्जन बिहारी लड़के काम कर रहे हैं। हर आधे एक घन्टे बाद विभिन्न थानों की पुलिस व सी आई ए वाले पहुंच कर अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही नंगा खेल 3 नम्बर डी ए वी कॉलेज के सामने बने पार्क में भी शराब माफ़िया अन्नू चुन्नी कर रहे हैं व इन दोनों भाइयों ने राहुल कॉलोनी में भी अपने कई अड्डे बनाये हुए हैं

यहां पाठकों को बता दें कि एन आई टी 5 नम्बर सी ब्लॉक में पाला सरदार गगन व हरबंस बीच सड़क में कुर्सी लगाकर सट्टे की पर्चीयां व शराब धड़ल्ले से बेच रहे हैं। नम्बर 5 के/2 ए में बीच सड़क पर आशू खत्री व बिट्टू भी शराब का धंधा खुले में कर रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन रोड पर काका साईकिल स्टैंड पर काका भी बीच सड़क में सट्टे की पर्ची लिख कर शहर के बच्चों व युवाओं को बर्बाद करने पर तुला हुआ है जबकि थाना एनआईटी से काका का अड्डा कुछ ही दूरी पर है एक शराब माफ़िया ने बताया कि थाना एनआईटी पुलिस सट्टे की पर्ची की मंथली 15000 रुपये महीने व शराब तस्करी के लिये 10 000 हज़ार रुपये महीना लेती है। इसके अलावा ये ही माफ़िया अपने विरुद्ध पुलिस को हर महीने एक दो केस भी देते हैं। ठीक इसी तरह डी सी पी एनआईटी व ए सी पी एनआईटी का दफ़्तर जिस एल ब्लॉक में है। वहां दिन दहाड़े वेश्यावृत्ति का धंधा जम कर चल रहा है।

नगर निगम, 'हूडा' के तोड़फ़ोड़ कारोबार से पुलिस पर बढी बेगार

फ़रीदाबाद (म.मो.) नगर निगम, 'हूडा' व इनके सहायक विभाग नगर योजनाकार ने बाकायदा अपने-अपने तोड़फ़ोड़ दस्ते गठित कर रखे हैं। ये दस्ते आये दिन कहीं न कहीं तोड़फ़ोड़ का अभियान चलाये रखते हैं जिसके लिये अच्छा-खासा पुलिस बल तैनात किया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इनके द्वारा तोड़ा-फ़ोड़ा गया एक भी निर्माण ऐसा नहीं है जिसका पुनर्निमाण न हो गया हो और उसे सम्बन्धित अधिकारियों ने स्वीकार न कर लिया हो। जाहिर है यह पैसे कमाने का खेल है।

आजकल 'हूडा' विभाग तोड़-फ़ोड़ का नाटक बाइपास रोड पर खेल रहा है। वह भी मात्र एक छोटे से हिस्से में बनी छोटी-मोटी दुकानों एवं खोखों आदि पर। बड़े-बड़े शोरूम ऊंची आलीशान ईमारतों की तरफ़ तो कोई झांकता तक नहीं है। अधिकांश निर्माण 'हूडा' की उस ज़मीन पर हुए हैं जिनका मुआवज़ा अदा करके बरसों पहले 'हूडा' ने अधिग्रहण कर लिया था। कुछ ज़मीन नहर विभाग की भी है जिसे मुआवज़ा देकर इस विभाग ने बरसों पहले अधिग्रहीत किया था। यहां दोनों विभागों की मिलीभगत एवं रिश्वतखोरी के बल पर ही तमाम निर्माण कार्य हुए हैं।

फ़िलहाल जो तोड़-फ़ोड़ का नाटक बाईपास पर चल रहा है, उसका उद्देश्य अतिक्रमण हटाना कतई नहीं है, केवल तोड़-फ़ोड़ का डर दिखा कर उनसे पैसा ऐंठना है। दूसरे, इस नाटकबाज़ी की आड़ में सड़क के साथ-साथ फुटपाथ व साइकिल ट्रैक का बजट पास कराना है। जब बजट आ जायेगा तो निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा तथा कहीं न कहीं अतिक्रमण के बहाने काम रोक दिया जायेगा। फ़िर अतिक्रमण हटाने व बनाने के नाम पर बजट को डकार लिया जायेगा।

सारे धंधे में पुलिस की भूमिका बड़ी अहम है। पुलिस की धौंस से ही यह सारा करोबार चलता आ रहा है। पुलिस के उच्चाधिकारियों को चाहिये कि वे इन विभागों से साफ़ बात करके सर्वप्रथम अतिक्रमणकारी के विरुद्ध फ़ौजदारी मुकदमे दर्ज करें, दूसरे, बजाय किसी भवन का नाम-मात्र को थोड़ा सा किनारा तोड़ने के उसे पूरा ध्वस्त करायें और तीसरे, मलबे को नीलाम करके तोड़-फ़ोड़ पर हुए खर्च की वसूली की जाय। जिस दिन सरकार ने यह व्यवस्था लागू कर दी, उस दिन अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण बिल्कुल बंद हो जायेंगे। फ़िर न तोड़-फ़ोड़ दस्ते की जरूरत रहेगी और न ही पुलिस को यह बेगार झेलनी पड़ेगी। लेकिन तोड़-फ़ोड़ महकमों की कमाई का फ़िर क्या होगा?

अटाली की 'आग' बुझ नहीं रही, तनाव और बहिष्कार जारी

बल्लबगढ (म.मो.) अटाली गांव में 25 मई को भड़की साम्प्रदायिकता की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जानकार इसे आगामी पंचायत चुनाव से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि चुनाव तक यह इसी तरह सुलगती रहेगी।

25 मई की घटनाओं से भयभीत होकर, जान बचा कर, थाना शहर में करीब 10 दिन तक शरण लिये रहने के बाद तमाम मुस्लिम परिवार गांव तो लौट गये लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सैंकड़ों पुलिसकर्मी वहां 24 घंटे तैनात हैं। 25 जून को तनाव थोड़ा बढने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया। पुलिस के साये में बनी इस शान्ति को स्थाई नहीं माना जा सकता। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्गों के बीच पड़ चुकी दरार पटने की बजाय चौड़ी होती जा रही है। पहले जहां दोनों समुदाय मिल जुलकर रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे; अब वह बात नहीं रह गयी है।

अल्पसंख्यक समुदाय के नाई से कोई बाल नहीं कटवाता, उनके ऑटो में बैठ कर कोई शहर नहीं जाता, उनकी भैंसा बुग्गी में अब कोई सामान नहीं लदवाता, उनके किसी कामगार से कोई काम नहीं कराता। ऐसे में ये लोग पूरी तरह से बेरोज़गार हो गये हैं। जाहिर है काम के बिना कोई कब तक रह सकता है। और तो और बहुसंख्यक समुदाय का कोई दुकानदार इनसे कोई लेन-देन नहीं करता। इसी तरह इनकी भी किसी दुकान से दूसरा कोई सम्बन्ध नहीं रखता। यद्यपि इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है लेकिन अल्पसंख्यक बताते हैं कि यह सब एक पंचायती फ़ैसले के तहत हो रहा है। इसमें कहा गया है कि उल्लंघन करने वाले पर 1100 रुपये तक का जुर्माना किया जायेगा।

जानकार बताते हैं कि 5 वर्ष पूर्व भी चुनाव के समय, बेशक इतना नहीं, माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था। लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जिस तरह का चुपचाप तनाव बना हुआ है इसमें प्रशासन भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। प्रशासन किसी को किसी से बाल काटने, उनके ऑटो में सवारी करने अथवा उनसे कोई सम्बन्ध रखने के लिये किसी क़ानून के अभाव में बाध्य नहीं कर सकता। मुख्य मामला यानी मस्जिद बनाने का मसला, अदालती स्टे से चालित है और अदालतों को कोई जल्दी नहीं होती।

स्थिति पर नज़र रख रहे जानकारों का कहना है कि दोनों समुदाय में छाया युद्ध जैसी पैंतरेबाज़ी चल रही है। बहुसंख्यक समुदाय की सोच है कि उन पर दर्ज मुकदमे खत्म हों और मस्जिद भी गांव से बाहर बने। अल्पसंख्यक समुदाय की सोच है कि मस्जिद जहां की तहां रहे और उन पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटें। चुनावी राजनीति इस ठहराव को टूटने नहीं दे रही।

आबकारी विभाग ने छापा मारकर भारी मात्रा में शराब पकड़ी

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 25 जून को 5 सी 48 निवासी नीतिन शर्मा उर्फ़ अत्ति के घर पर छापा मारकर आबकारी विभाग ने 114 पेटी बीयर (बोतल), 32 पेटी केन बियर 179 बोतल महंगी अंग्रेजी शराब तथा सैंकड़ों अध्धे पौवे पकड़े। इस बाबत पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस नोट में दावा किया गया है कि उक्त छापामारी पुलिस ने की है। जबकि यह सरासर झूठ है। पुलिस इस माफ़िया को पकड़ने की अपेक्षा सदैव इससे हफ़्ता वसूली करती रही है।

2 अप्रैल को भी इसी शराब माफ़िया पर आबकारी विभाग ने छापा मारकर भारी मात्रा में शराब पकड़ी थी। इसके अलावा भी दर्जनों शराब माफ़िया 5 नम्बर गांधी कॉलोनी व फतहपुर चंदीला गांव में धड़ल्ले से शराब का धन्धा खुलेआम कर रहे हैं। जाहिर है यह सब पुलिस के संरक्षण में ही संभव है।

कासनी ने हिसाब मांगा तो पत्ता कटा

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ईमानदार प्रशासन लाने के नाम पर जितने मर्जी हाथ पांव चला लें, खट्टर सरकार का खटराग बदस्तूर जारी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के डी जी प्रदीप कासनी की गिनती ईमानदार अधिकारियों में की जाती है। यह महकमा स्वास्थ्य मंत्री विज के आधीन ही आता है। पिछले दिनों जैसे ही कासनी ने करनाल में बन रहे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की प्रगति की समीक्षा करनी चाही, उन्हें तबादले के रूप में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ताकि दूसरों के लिये भी सबक रहे। उन्हें भेजा गया है पुरातत्व जैसे महत्वहीन समझे जाने वाले विभाग में।

'मज़दूर मोर्चा' कई मौकों पर लिख चुका है कि खट्टर मंत्रिमंडल में एक मात्र ईमानदार मन्त्री अनिल विज की आवाज नक्कारखाने में तूती वाली है। पाठकों को याद दिला दें कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को परिवहन मन्त्रालय से ट्रांसपोर्ट माफ़िया के दबाव में बदला गया था। उस अवसर पर विज ने खुले रूप में खेमका का पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री खट्टर के समक्ष मामला उठाने का साहस किया था। तब भी वे कुछ करा नहीं पाये थे। आज उनके ही महकमे के ईमानदार अधिकारी के बदले जाने पर उनकी अपनी बोलती बंद पड़ी है। हवा का रूख भला और कैसे दिखाई पड़ेगा?

मेडिकल कॉलेजों को चलवाने वाले राजनेता भी हैं

मजदूर मोर्चा, ब्यूरो। केरल के पेरिपल्ली व तमिलनाडू के कोयम्बटूर में भी ईएसआई निगम ने फ़रीदाबाद जैसे मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बना कर खड़े कर दिये हैं लेकिन उन्हें चलाने का कोई इरादा नहीं है। न खुद चला रहे हैं न राज्य सरकार को चलाने दे रहे हैं। लेकिन वहां की सरकारें व सांसद यहां की तरह नालायक व निकम्मे नहीं हैं। उन्होंने मिल कर वहां पुरज़ोर मुहिम चला रखी है कि इसी सत्र से कॉलेज में दाखिला शुरू हो। विदित है कि कोयम्बटूर में 5 लाख और पेरिपल्ली में एक लाख बीमाकृत मज़दूर हैं। उनका दबाव इतना भारी है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय व श्रम मन्त्रालय को झुकना पड़ेगा। संदर्भवश यह भी जान लेना चाहिये कि सरकार की नालायकी के चलते इस वर्ष देश भर में मेडिकल कॉलेजों में 600 सीटें कम होने जा रही हैं, जबकि भाजपाई सरकारें देश में डॉक्टरों की संख्या बढाने का ढोल पीट रही हैं।